remaining species is strictly regulated according to the condition of the licence granted for this purpose.

(iii) International trade in endangered species of plants and animals and articles made thereof, is regulated under the provisions of the Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

(iv) Central assistance is provided to State/UT Governments for strengthening anti-poaching infrastructure..

(v) A network of 418 wildlife sanctuaries and 74 national parks covering 4.2% of the geographical area of the country, has been set up tor conservation of wild flora and fauna. Financial assistance is provided by the Central Government for development of national parks and sanctuaries, on request from the State Governments,

(vi) Special schemes for protection and conservation of tigers and elephants are being implemented,

(vii) A system of cash rewards has been introduced for getting intelligence about poachers and illegal traders.

(viii) Raids are carried out by the Wildlife Authorities whenever information of illegal trading in animals, is received.

(ix) Cooperation of Customs, Revenue Intelligence, Coast Guard and Army authorities is being taken in apprehending the poachers and illegal traders,

(d) No amendment to Wild Life (Protection) Act is under consideration of the Government at present. Information regarding cases of rllegal trade in wildlife products detected by the Directorate of Wildlife Preservation through its regional centres during three years is set out below:

Year	Number of cases detected
1989	99
1990	122
1991	123

The information about cases filed and decided is being collected and will be laid on the Table of the House.

Genetic/species thefts from Indian forests

3357. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that cases of genetic /species thefts from the Indian Forests are on the increase; and

(b) What legislative and administrative measures are being taken by Government to prevent such thefts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) While occassional cases of species thefts come to the notice of Central Government, State Wildlife Authorities have not reported any general increase in the incidence of such thefts.

(b) Legislative and administrative measures being taken by Government to prevent such thefts are as under:

(i) The Indian Forest Act, 1927 has been amended from time to time in order to keep the threat of theft of forestry species and forest products under control.

(ii) The Wild Life (Protection) Act was passed in 1972 and has been amended time to time and a comprehensive amendment was brought about in 1991 in order to make to law more stringent and deterrent for thieves and smugglers.

(iii) International trade in endangered species plants and animals and articles made thereof, is regulated under the provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

(iv) A network of 418 wildlife sanctuaries and 74 national parks

covering 4.2% of the geographical area of the country, has been set up for conservation of wild flora and fauna. Financial assistance is provided by the Central Government for development of national parks and sanctuaries.

(v) Special Schemes for protection and conservation of tigers and elephants arc being implemented.

(vi) A system of cash rewards has been introduced for getting intellignece about poachers and illegal traders.

(vii) Raids are carried out by the Wildlife Authorities whenever information of illegal trading in animals is received.

(viii) Cooperation of Customs. Revenue intelligence. Coast Guard and Army authorities is being taken in apprehending the poachers and illegal traders.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3358. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन कर दिया है;

(ख) देश में कुल कितने और किस प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में कितने बोर्डों का गठन किये जाने की संभावना है;

(ग) इन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का स्वरूप क्या होगा और क्या इन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में पर्यावरण विशेषज्ञों, न्यायविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जायेगा; और

(घ) इस बोर्ड के क्या कार्य हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा, भारत संघ के सभी 25 राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं। लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां कार्य कर रही हैं।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 का उप धारा (2) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 की उप धारा (2) के अनुसार एक राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष जो पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा (अध्यक्ष पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, हो सकता है);
2. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित पदधारी, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी;
3. पांच व्यक्ति, जो राज्य के भीतर कृत्य करने वाले स्थानीय अधिकरणों के सदस्यों में से उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
4. तीन अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार के या किसी अन्य हित का जिसका राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
5. राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधत्व करने के लिए दो व्यक्ति जो उस सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;
6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, जिसकी अहर्ताएं, ज्ञान एवं अनुभव, प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियरी या प्रबन्धन पक्षों से संबंधित हों।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. राज्य में सरिताओं और कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना;
2. जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना;
3. जल प्रदूषण और उसके निवारण, नियंत्रण या